भरोसा खुदपर रखो तो ताकत बन जाती है दूसरों पर रखो तो कमजोरी।
– अज्ञात

विचार-प्रवाह

देहरादून रविवार 12 जनवरी 2020

पेज थ्री
www.page3news.in

भारत बंद का मिला-जुला असर

बैकों के कर्मचारी पब्लिक सेक्टर बैंकों के विलय का विरोध कर रहे हैं। मांगपत्र में आम लोगों की जरूरत वाली चीजों के बढ़ते दाम को काबू करना, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाना और बेरोजगारी दूर करना भी शामिल है।

गौरव प्रधान।

बुधवार को ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का मिला–जुला असर रहा। देशभर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर रेल और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा। कुछ जगहों पर, खासकर पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ पुलिस की झड़पों की खबरें भी आई हैं लेकिन हिंसा की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। बंद का आह्वान 10 ट्रेड यूनियनों ने किया था और इसे कई किसान संगठनों और छात्र संगठनों के अलावा कई विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया था। श्रम संगठनों का कहना था कि उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल की है। वे लेबर लॉ में प्रस्तावित संशोधन के भी खिलाफ हैं। उनकी मांग है कि मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई जाए, उन्हें सोशल हेल्थ सर्विस में शामिल किया जाए, साथ ही उन्हें मिड डे मील और 6000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिले।

बैकों के कर्मचारी पब्लिक सेक्टर बैंकों के विलय का विरोध कर रहे हैं। मांगपत्र में आम लोगों की जरूरत वाली चीजों के बढ़ते दाम को काबू करना, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाना और बेरोजगारी दूर करना भी शामिल है। यह बंद ऐसे समय में किया गया है जब देश की अर्थव्यवस्था गंभीर मुश्किलों का सामना कर रही है। हमारी विकास दर ठिठक गई है। बाजार में नई मांग नहीं पैदा हो पा रही है। नौकरियों का हाल बुरा है क्योंकि अधिक रोजगार वाले सेक्टरों में भारी मंदी है। कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों की छंटनी की खबरें लगातार आ रही हैं। विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने को लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखा रहे। निर्यात कमजोर पड़ रहा है और टैक्स की वसूली उम्मीद से कम हो रही है। इन हालात के लिए अकेले सरकार जिम्मेदार नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी यह संकट पैदा किया है। स्लोडाउन पूरी दुनिया में है। अमेरिका और चीन में जारी ट्रेड वॉर ने संकट बढ़ाने का काम किया है, ऊपर से कोढ़ में खाज की तरह खाड़ी में तनाव और पैदा हो गया है। इस वजह से पेट्रो पदार्थों के दाम बढ़े तो हालात भयावह हो सकते हैं। ऐसे में पहली जरूरत यह है कि न सिर्फ मजदूरों–कर्मचारियों, बल्कि हर तबके के साथ सरकार का संवाद अच्छा हो। कोई छोटा गतिरोध भी अभी के माहौल में बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ असंतुष्ट तबकों को भी बातचीत की गुंजाइश ज्यादा रखनी होगी। काम चलता रहेगा तो बेहतरी की लड़ाई जारी रहेगी। काम ही ठप हो गया तो कोई किस बात के लिए किससे लड़ेगा?

सरकार के साथ समस्या यह है कि खुद को मिले चुनावी समर्थन को वह अपनी हर नीति पर जनता की मुहर मानकर चल रही है और बड़े फैसलों से पहले संबद्ध पक्षों की राय लेना उसे जरूरी नहीं लग रहा। लेकिन संकट के समय लोगों को भरोसे में लेने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। बेहतर होगा कि सरकार ट्रेड यूनियनों से बात करती रहे और श्बंदश जैसी नौबत देश के सामने बिल्कुल न आए।

सूत्रपात

योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी।

धर्म-दर्शन

गोकुल के ग्रामों से अथक संघर्ष के साथ भगवान श्रीकृष्ण द्वारा किये गये ग्राम स्वराज के सूत्रपात ने ही कभी महाभारत का रूप लिया, तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने इसी स्वराज अभियान को जन–जन में स्थापित करने का आन्दोलन चलाया और भारत विश्व गौरव की ओर बढ़ चला। सम्पूर्ण विश्व ने उस भारत से प्रेरणायें लीं। इसे अपना मार्गदर्शक मानते हुए उन सूत्रों से अपने–अपने देश को खुशहाल बनाया, उन्हीं जीवन एवं समाज निर्माण के स्वराज सूत्रों के चलते भारत लम्बे कालतक विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहा। कालांतर में परिस्थितियां बदलीं। मूल्यों में क्षरण हुआ। व्यावसायिकता की चकाचौंध में आवश्यकतानुरूप खड़े किये गये नगरों ने जब गांवों के प्रति अपना दायित्व निभाना बंद किया, तो वही भारत इतना कमजोर–जर्जर हो उठा कि उसे सैकड़ों सालों तक गुलामी के दंश झेलने पड़े।

संपादकीय

प्रसन्न समाजों की सूची

यह वाकई चिंता की बात है कि प्रसन्न समाजों की सूची में पहले ही काफी नीचे चल रहा हमारा देश अभी थोड़ा और नीचे खिसक गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान 140वां है जबकि पिछले साल वह 133वें स्थान पर था। पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित अपने ज्यादातर पड़ोसी समाजों से कम खुश है भारतीय समाज। रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार दूसरे साल सबसे खुशहाल देश का तमगा मिला, इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क का नाम है। खुशहाली के मामले में सबसे अंतिम पायदान पर बुरुंडी का नाम है। इस सूचकांक के लिए अर्थशास्त्रियों की एक टीम समाज में सुशासन, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, जीवित रहने की उम्र, भरोसा, सामाजिक सहयोग, स्वतंत्रता और उदारता आदि को आधार बनाती है। रिपोर्ट का मकसद विभिन्न देशों के शासकों को आईना दिखाना है कि उनकी नीतियां लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाने में कोई भूमिका निभा रही हैं या नहीं। जहां तक भारत का प्रश्न है, पिछले कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। अनेक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों ने इस मामले में हमारी पीठ ठोकी है। यही नहीं, खुद संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों को रेखांकित किया है। बावजूद इसके, खुशहाली में हमारा मुकाम इतना नीचे होना हैरत में डालता है। दरअसल पिछले दो–ढाई दशकों में भारत में विकास प्रक्रिया अपने साथ हर मामले में बहुत ज्यादा विषमता लेकर आई है। जो पहले से समर्थ थे, वे इस प्रक्रिया में और ताकतवर हो गए हैं। एकदम साधारण आदमी का जीवन भी बदला है लेकिन कई तरह की नई समस्याएं उसके सामने आ खड़ी हुई हैं।

इस चुनाव में सीएए को लेकर जारी बहस और जामिया मिलिया व जेएनयू में हुई हिंसा की छाया पड़ने की संभावना है।

चुनाव का बिगुल बजा

पूनम यादव।

दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 8 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। पिछले दो विधानसभा चुनाव यहां आम आदमी पार्टी के पक्ष में एकतरफा या उसके और बीजेपी के बीच आमने–सामने के रहे हैं। इस बार कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल के उभार के साथ दिल्ली की सियासत में अपेक्षाकृत युवा नेताओं का दबदबा बढ़ गया है। यहां की राजनीति पर प्रभाव रखने वाले पुराने नेताओं में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, मोटे तौर पर कहें तो लगभग सारे ही जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी में तकरीबन सारे युवा हैं। कांग्रेस में अजय माकन के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सुभाष चोपड़ा ने कमान संभाली है। बीजेपी से कांग्रेस में पहुंचे कीर्ति आजाद की भूमिका भी अहम हो सकती है। बीजेपी में डॉ. हर्षवर्धन और विजय गोयल सीनियर हैं, लेकिन कमान युवा पूर्वांचली नेता मनोज तिवारी के हाथ में है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सक्रियता को भी गौर से देखा जा रहा है, जो दिल्ली की राजनीति में नए हैं। राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती पर भारतीय राजनीति का केंद्र होने के कारण इन मुद्दों का असर यहां जरूर होगा। इस चुनाव में सीएए को लेकर जारी बहस और जामिया मिलिया व जेएनयू में हुई हिंसा की छाया पड़ने की संभावना है।

आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार के कामों के आधार पर वोट मांगने जा रही है, जिसे लेकर वह काफी आश्वस्त है। बीजेपी की दुविधा यह है कि पिछले कुछ असेंबली चुनावों में मोदी मैजिक नहीं चल पाया है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के कार्यों में खोट दिखाकर वह बेहतर गवर्नेंस का दावा भी कर रही है। मुश्किल यह है कि उसके पास सुशासन का कोई ताजा मॉडल नहीं है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के हाथों खोई अपनी जमीन वापस पानी है। 2015 में आम आदमी पार्टी को रेकॉर्ड 54.34 फीसदी वोट मिले थे, जिनमें ज्यादातर कांग्रेस के थे। अगर बीजेपी को देखें तो उसके वोट कमोबेश ज्यों के त्यों रहे हैं।

2013 के चुनाव में उसने 31 सीटें जीती थीं और वोट मिले थे 33.07 फीसदी, जबकि 2015 में उसकी सीटें घटकर सिर्फ 3 रह गईं लेकिन वोट परसेंट 32.19 रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने अपना वोट शेयर सुधारा, वह आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। 2014 में कांग्रेस को केवल 15 पर्सेंट वोट मिले थे जबकि 2019 में उसका वोट शेयर 22.5 फीसदी पर आ गया। यह ट्रेंड जारी रहा तो आम आदमी पार्टी के लिए समस्या हो सकती है, हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का ट्रेंड एक सा नहीं होता। 2019 में 'आप' 18 प्रतिशत पर जबकि बीजेपी 57 पर्सेंट पर पहुंच गई। देखें, दिल्ली का वोटर किस मिजाज से वोट देता है।

सूडोकु नवताल- 5220

★★★★☆ मध्यम

		5			8			3
	7			3	5			
3						6		
							8	5
	6			7			1	
4	2							
		1						8
			7	4			3	
6			2			7		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5219 का हल

9	4	8	7	5	1	6	2	3
3	7	5	6	4	2	1	8	9
6	2	1	3	9	8	4	7	5
4	1	3	8	6	7	9	5	2
5	8	6	9	2	4	3	1	7
2	9	7	5	1	3	8	4	6
8	6	4	2	7	9	5	3	1
7	3	9	1	8	5	2	6	4
1	5	2	4	3	6	7	9	8

अपना ब्लॉग

बंगाल में साझा सरकार का विफल प्रयोग

रौशन कुमार झा। आजादी के बाद हुए तीन आम चुनावों में कांग्रेस पश्चिम बंगाल में छाई रही, परंतु पश्चिम बंगाल कांग्रेस में आरंभ से ही अनेक महत्वपूर्ण आंतरिक समस्याएं थीं। जहां अतुल घोष तथा प्रफुल चंद्र सेन एक ओर थे, वहीं अरुण चंद्र गुहा, सुरेंद्र मोहन बोस और प्रफुल्ल चंद्र घोष दूसरी तरफ थे। मेरे पिता ने अतुल घोष के साथ काम किया था। वे 1948 से पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी के सदस्य थे। अंततः 1966 में पश्चिम बंगाल कांग्रेस में दरार आई। अजय मुखर्जी के नेतृत्व में एक दल अलग से काम करने लगा। एक मई 1966 को औपचारिक रूप से बांग्ला कांग्रेस की स्थापना हुई। इस दल के गठन की प्रक्रिया के दौरान के दौरान ही अजय बाबू ने श्याम स्क्वायर कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा बुलाई थी। मैंने भी उस में हिस्सा लिया, हालांकि तब मैं नियमित कांग्रेसी नहीं था। 8 जून 1966 को मैं अजय बाबू के साथ राज्य के दौरे पर था। उसी दौरान मैंने उन्हें संयुक्त मोर्चा के गठन का सुझाव दिया था, 'अजय दा, यदि हम कांग्रेस को पराजित करना चाहते हैं तो हमें सभी दलों को एक करना होगा।